डा० राम सुभग सिंह : कहां बोल रहा हूं ? आप भी तो रपट इत्यादि कहते हैं । एक भी शब्द अंग्रेजी का मत रखिये ।

14.14 hrs.

STATEMENT RE. DELAY IN THE ARRIVAL OF FOOD SHIPS IN INDIA DUE TO CLOSURE OF SUEZ CANAL—contd.

Mr. Deputy-Speaker: Members wanted to put questions on the statement of the Food Minister.

Shri Hem Barua: Now the West Asian situation has taken a dramatic turn after the acceptance of the UN cease-fire resolution by both the warring parties and yet unfortunately the Suez Canal is not open for navigation and also in view of the fact that famine is stalking our land, what steps have the Government taken or propose to take through the UN to see that the Suez Canal is reopened forthwith so that the food ships coming from America might come straight to our country in order to meet the distressing situation?

Shri Jagjiwan Ram: Now that the ceasefire has been accepted, efforts will be made in the UN and our representatives will also try to normalise the situation so that the foodships may come.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : स्वेज नहर के पर कुछ बोलते हुए थोड़ा सा डर लगता है । डर जितना सही है उससे ज्यादा भूत जैसा है । इसका कारण यह है कि हम लोग सब यहां पर नीति एक ही अपनाये हुए हैं । लेकिन फिर भी बोली में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है । जितने आदमी हैं सब की एक ही नीति है । किसी ने यहां नहीं कहा कि एक आदमी अरब भेजो, या हवाईजहाज भेजो, या एक सिपाही या एक एम्बुलेंस भेजो या कुछ दो भेजो । लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई बार हम लोगों में इतनी मर्मी बोली की आ जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई नीति का बड़ा भारी फर्क है । लेकिन आपकी बोली का फर्क है, नीति का फर्क नहीं है । यह मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं । मैं तो इससे भी आगे जाता हूं । सामने वाले पक्ष और इस पक्ष में भी नीति का कोई फर्क नहीं । दोनों तरफ के लोगों ने एक ही बात कही और कह रहे हैं । कह रहे हैं कि कोई आदमी मत भेजो, कोई सिपाही मत भेजो, कोई दवाई मत भेजो, कोई एम्बुलेंस मत भेजो, कोई मोमी मत भेजो । दोनों पक्षों के अलग रहते हुए भी नीति एक ही है । लेकिन इस बोली के फर्क से मुझ को एक बड़ी चिन्ता लग गई है । इतने दिनों से जो मैं यह सोच रहा हूं कि विरोध पक्ष का एका हो जाए और इस बारे में जो सपना ले रहा हूं, उस सपने को मालूम होता है कि थोड़े दिन के लिए मुझको छोड़ना पड़ेगा । जब मैं यह कह रहा हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप भी अमरीकी गेहूं और स्वेज नहर का सपना छोड़ें । मैं बड़ी गम्भीरता से उनके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं ।

क्या हम लोग सब मिल कर इस जून महीने में और जुलाई महीने में ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकते हैं कि जिससे जितनी इस समय बरसाती खेती हो सकती हो करें । जहां जहां पहले से नहरें हैं उनके अलावा कम से कम 40–50 लाख या 1 करोड़ एकड़ भूमि बिल्कुल पानी के नीचे आ जाए क्या हम इसकी कोशिश नहीं कर सकते हैं ? मैं समाजवादी युवा जन सभा की तरफ से कहने को तैयार हूं कि स्वयं सेवक काफी तादाद में आपको मिलेंगे । मैं समझता हूं कि हर एक पार्टी इसके लिए तैयार है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं कि हमारे चेयरमैन जोशी साहब से इस सम्बन्ध में बातचीत करें– और उसी तरह से और दलों के लोगों से बातचीत करें । ऐसे स्वयं सेवक जो सिगरेट और चाय में पैसा नहीं उड़ायें आपको मिल सकते हैं । ऐसे मिल सकते हैं जो दो दो

सौ मील चल कर न जायें। एक मील आध मील की दूरी पर रहते हों। लाखों की संख्या में स्वयं सेवकों को लगा कर . . .

Mr. Deputy-Speaker: The point in the statement is regarding delay in arrival of the Indian shipments to India. This is a limited question.

डा० राम मनोहर लोहिया : वही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। जहाज नहीं आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, गेहूं नहीं आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। मैं आप से इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि दोनों ताशकन्दी सेट—आप समझ ही गए होंगे—थानी रूस और अमरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मंत्री महोदय सोच रहे हैं, वह पूरा न हो और जो वह कह रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगी, न आए। हाजी-मीर को खाली करवाना आसान था दोनों ताशकन्दी सेठों के लिये लेकिन शर्म एल शेख को खाली करवाना मुश्किल होगा। फिर यह जुलाई में भी नहीं आएगी अगस्त में भी नहीं आएगी। मैं उसी सम्बन्ध में सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हम लोग अपने देश में अपने पुरुषार्थ से अपने स्वयं सेवकों के द्वारा इस तरह की खेती करवाने की तरफ ध्यान देंगे? मैं इस वक्त कोई मामूली बात नहीं बोल रहा हूं। मैं विरोधी पक्ष के एक एक के सपने की बात फिलहाल छोड़ कर बोल रहा हूं। सब को मिल कर, स्वयं सेवकों के द्वारा क्या हम अगले दो महीनों में अन्न की पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं? एक करोड़ न सही, 50 लाख टन अतिरिक्त पैदावार अपने यहां दो चार या छः आठ सप्ताहों में आप खेती कर लें, क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हमारे सभापति से बात करने के लिए तैयार हैं?

श्री जगजीवन राम : मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने आरम्भ से ही यह कहा है कि हमारी खाद्य समस्या का एक ही हल है कि हम अपने देश में उतना अनाज पैदा करें कि हमको दूसरे किसी देश से मंगाने की आवश्यकता न पड़े। मैं ने यह भी कहा है कि जितने भी सार्वजनिक नेता हैं, समाज सेवक हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं सब के सहयोग से इस देश में ऐसा अभियान चले जिस से किसानों में एक नई चेतना पैदा हो, जहां कहीं भी पानी उपलब्ध है या छोटी स्कीम चला कर पानी उपलब्ध किया जा सकता है वहीं पानी उपलब्ध किया जाए, और जमीनों की जुताई और बुवाई हो जाए ताकि इस साल हम काफी पैदावार कर सकें। मैं आप के नेता से भी बात करूंगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : आज शाम को ही शुरू कर दीं यह बात।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): स्टेटमेंट में कहा गया है कि जहाज आने में कुछ देर लगेगी, क्योंकि उन को दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा। स्वेज कैनाल को बन्द हुए कुछ दिन तो बीत गए। शायद इस में कुछ और दिन लगें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में हमें कितने अनाज की, कितने चावल और गेहूं की, कमी पड़ेगी। मंत्री महोदय ने स्टेट्स को रीएलोकेशन करने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को कुछ कम अनाज देना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टेट्स को कितना कम अनाज दिया जायेगा। क्या सरकार ने इस कमी को किसी तरह से पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था की है? क्या मंत्री महोदय ने स्टेट्स की सरकारों को इस बारे में लिखा है?

श्री जगजीवन राम : ये घटनायें बहुत तेजी से घटित हुई हैं। अभी तक तो हम यह अन्दाज लगा सकते हैं, कि इस महीने में हम को जितना अनाज आना चाहिए था, सम्भवतः उस में ढाई लाख टन कम आयेगा। मैंने कल ही सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को तार भेजे हैं। इस के साथ ही हम अपने मंत्रालय में यह देख रहे हैं कि कहां पर कितनी कमी

[श्री जगजीवन राम]

कर के हम काम चला सकते हैं। लेकिन दो एक दिन के बाद नक्शा और भी साफ़ हो जायगा। हमारे पास जितना अनाज कम पड़गा, हमें उस के हिसाब से प्रान्तों को कुछ कम दे कर काम चलाना पड़ेगा।

Shri Inderjit Gupta (Alipore): The statement says that there is a quantity of 2½ lakh tons which is actually at sea now on the vassels which have already left and "to that extent the allotment of foodgrains for this month will have to be revised". There must be some advance thinking in the ministry about the basis of this revision, how the priorities must be fixed and so on. They cannot go on waiting for that; they must be thinking now because it is a question of allocations for the current month. On what basis are you going to fix the priorities while revising the allocation to the extent of 2-1|2 lakh tons?

Shr Jagjiwan Ram: The simplest way may be to apply a uniform percentage cut in the allocations for all the States. But in addition to that, special circumstances in some States will have to be taken into consideration while making a cut in the allocations already made.

Shri Vasudevan Nair (Peermade): The statements is alarming and disturbing, especially for those who come from deficit States and who are in need of central supplies. I hope the statement was prepared before the Government received news of the cease-fire and they will make a re-assessment of the situation. In spite of that, may I know whether the Government are thinking of tightening up the procurement machinery inside the country as much as possible on a war footing so that in the new situation, we can procure more foodgrains from inside the country? What steps do they propose to take in that direction?

Shri Jagjiwan Ram: I have always been emphasising the necessity of having procurement in both the surplus and deficit States. Yesterday morning we were thinking of convening an emergent meeting of the State Chief Ministers. Now the situation having changed after the cease-fire having been accepted, let us hope that the Suez Canal will be re-opened very quickly. In any case, I am thinking of convening a meeting of the Standing Committee of the Chief Ministers' Conference to consider all these problems. I will take this opportunity to appeal to all State Governments, both deficit and surplus, to intensify the procurement measures in their States.

Shri Sequeira (Goa, Daman and Diu): Arising out of the reply he has just given, may I know whether at this conference which he is convening, he will consider suggesting to the Chief Ministers of surplus States that whatever stocks they procure locally should be controlled and distributed by the Central Government equitably to all the States?

Shri Jagjiwan Ram: As a matter of of fact, even under the present arrangement, whatever surplus is available in a surplus State after meeting their own requirement, that is placed at the disposal of the Central Government to be allocated to the deficit States.

Shri R. K. Sinha (Faizabad): Dr. Lohia has suggested that efforts should be made to seek the cooperation of all parties to improve the food situation in the country. I want to make a suggestion to the Food Minister.

There should be an attempt to conscript the youth of this country, the students of this country and to mobilise the latent support for a solution of the food crisis. That is the sentiment in all the political parties of the country. I would, therefore, suggest to the hon. Minister of Food that an all-party conference, to which representative of the youth and students' organisations may be invited, may be convened of the Chief Ministers and some sort of a war council may be set up where a solution of the food problem may be sorted out so that we may not be in a position always to beg and borrow from abroad, and we may unfurl the banner of real independence because food is one of the dimensions of the freedom of the country.

Shri Jagjiwan Ram: As I have already said, I welcome the suggestion and to begin with I said I will call the leaders of the various parties in Parliament before we take in others.

डा० राम मनोहर लोहिया : मंत्री महोदय पहले तो हमारे जोशी साहब से मिलें और अकेले में मिलें ।

श्री जगजीवन राम : पहले उन से ही मिलेगा ।

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): Would the hon. Minister kindly confirm that the American Administration has not held up any of our food consignments on account of the West Asian crisis and the fact that our attitude and foreign policy in respect of Israel remains unchanged?

Shri Jagjiwan Ram: No, Sir, there has been no change or delay so far as the loading of ships in American ports is concerned.

श्री प्र० नं० सोलंकी (कैरा) : मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई तो इस देश में चल रही है—खाने के मामले में, कहीं और लड़ाई हो या न हो और स्वेज कैनाल के मामले ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि हमें अनाज पैदा कर जल्दी आत्म-निर्भर होना चाहिए । मैं समझता हूं कि जहां तक अनाज पैदा करने का सवाल है, हमें विद्यार्थियों या प्रोफसरों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है । इस के लिए आवश्यकता इस बात की है कि किसानों में विश्वास पैदा किया जाये ।

जो को-आपरेटिव सोसयटीज अनाज, शुगर और गुड़ का डिस्ट्रिब्यूशन करती हैं, वे प्राईवेट सैक्टर को बदनाम करती हैं, लेकिन वे स्वयं उस की तरह मुनाफाखोरी करने लगी हैं । इस कारण डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है । क्या मंत्री महोदय को-आपरेटिव सोसायटीज से बहुत जोर डाल कर यह कह सकते हैं कि चाहे कोई भी हालात हों, वे पैसे या मुनाफे का खयाल न करते हुए, जो कुछ भी स्टाक उन के पास है, उस को वे आम लोगों के लिए रखें और जरूरत पड़ने पर दें । मंत्री महोदय को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज डिस्ट्रिब्यूशन में ग़लती है । यह सरकार किसान में विश्वास पैदा करें—वह उस को पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा कर के देगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आज से दोनों को बदनाम करो ।

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं कह सकता हूं कि जितनी सहकारी समितियां हैं, उन सब पर यह बात लागू होती है ।

श्री प्र० नं० सोलंकी : सब नहीं, कुछ ।

श्री जगजीवन राम : बहुत सी सहकरी समितियों को-आपरेटिव सोसयटियों, ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वह काम प्रोडक्शन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो । लेकिन किसी भी जमाअत में कोई न कोई इस तरह के लोग होते हैं, जो अवांछनीय काम भी कर लिया करते हैं । हमारा बराबर यह प्रयत्न रहना चाहिए कि को-आपरेटिव

[श्री जगजीवन राम]

मूवमेंट में जो कुछ खामियां या कमजोरियां हैं, वे दुरुस्त हों, ताकि को-आपरेटिव मूवमेंट मजबूत हो कर तेजी से फैल जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अमरीका से तीस लाख टन गेहूं मिलने की बात थी और अभी अमरीका के राष्ट्रपति ने केवल पंद्रह लाख टन गेहूं देने पर हस्ताक्षर किये हैं। क्या यह आशा की जाये कि भारत सरकार जो पंद्रह लाख टन गेहूं चाहती है, वह मिलेगा, या वह खटाई में पड़ रहा है ?

श्री जगजीवन राम : उस के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह जो तीन मिलयिन टन देने की बात हुई, वह डेढ़ मिलियन टन कर के दो टुकड़ों में देने की बात थी। डेढ़ मिलियन टन के बारे में इस के बाद नेगोशिएशन्ज करने की बात होगी। हम उस के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम को आशा करनी चाहिए कि अमरीका इतने छुटपन पर नहीं उतरेगा कि वह वर्तमान झगड़े को इस मामले में ले आए।

श्री यशपाल शर्मा (अमृतसर) : अभी स्वैज के अन्दर जो राजनतिक परिस्थिति पैदा हुई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति फिर भी पैदा हो सकती है और इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने की ओर जो मंत्री महोदय का ध्यान सदन दिला रहा है उस भूमिका में से एक बात जानना चाहता हूं कि बचत के राज्यों के अन्दर उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए तात्कालिक कृषि संबंधी जो आवश्यकताएं हैं क्या इस चालू बजट के अन्दर खाद्य मंत्री महोदय बाकी और सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन बचत के राज्यों की भी जो उनकी आवश्यकताएं हैं और केन्द्र से जो उन की मांगें हैं उन को पूरा करवाने के लिए अन्य मंत्रालयों के ऊपर दबाव या सुझाव देंगे ?

श्री जगजीवन राम : मंत्रालयों के ऊपर दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री के भाषण को देखा होगा या उन के रवैये को देखा होगा तो मानना पड़ेगा कि सब कोई इस बात को महसूस करते हैं कि कृषि को सब से अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो जहां तक गुंजाइश होगी अधिक से अधिक धन कृषि पर खर्च कर सकें और खास कर के थोड़े समय में लाभ देने वाली स्कीमों पर खर्च कर सकें उस में कोताही नहीं की जायगी।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : अभी इजरायल और यू० ए० आर के संबंध में जिस तरह का स्टेटमेंट इस सरकार ने दिया क्या फूड मिनिस्टर इस बात को समझते हैं कि इस का असर जो फूड अमेरिका से मिलने वाला है उस पर पड़ेगा और यदि पड़ेगा तो उस के लिए देश में जो अनाज की कमी है उस को पूरा करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : इस का तो उत्तर अभी मैंने दिया वाजपेयी जी के प्रश्न का जवाब देते हुए और दूसरा जो प्रश्न है वह आम तौर से यहां उत्पादन बढ़ाकर ही और तीव्र गति से अगर उस को करें तो उस का मुकाबिला कर सकते हैं ?

Shri K. Narayana Rao (Bobbili): I want clarification on two points. I want to know whether the policy of procurement we have been adopting is a uniform policy both in the deficit as well as in the surplus States. This point is very relevant because certain States like West Bengal have stopped procurement because they are deficit States. That is one point. Secondly, the food policy and pricing here are consumer-oriented rather than producer-oriented with the result, as is mentioned in the budget speech. . . .

Mr. Deputy-Speaker: How is it connected with the blockade and delay in the arrival of foodgrains?

Shri K. Narayana Rao: We have been discussing the other point and the two are inter-connected.

Mr. Deputy-Speaker: He can ask questions only on the statement laid on the Table of the House.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): May I know whether this recent complication will affect in any way the total commitment that has been made by the consortium countries recently in their last meeting to give additional food aid, as America is doing? Is it likely to be disturbed?

Mr. Deputy-Speaker: That question has already been replied to.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I was asking about the consortium countries, not America; they have promised to give matching food aid.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): This discussion will make it more difficult. So, let us keep silent over it.

डा० राम मनोहर लोहिया : घर का भेदिया बुरा होता है मोरार जी भाई ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पश्चिमी एशिया में जो संकट पैदा हुआ है उस के संबंध में मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता लगता है कि देश में अनाज की दिक्कत होने वाली है । तो उस का हल निकालने के लिए माननीय सदस्य डा० लोहिया साहब ने एक प्रस्ताव रखा है कि हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करना चाहिए यह बात सही है पर मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जितना गल्ला पैदा हुआ है मुनाफाखोरों के पास, जखीरेबाजों के पास, चाहे वे देहात के अन्दर हों या शहर के अन्दर हो, मंत्री महोदय के पास क्या इस बात की कोई स्कीम है कि उनके पास से उस छिपे हुए गल्ले को निकालें और निकालकर जनता के बीच में दें और खास कर जिन इलाकों में अकाल है वहां ज्यादा से ज्यादा गल्ला भेजें न कि वहां गल्ला भेजने में कुछ कमी करें जैसे कि अन्दाज लग रहा है कि यह कुछ कमी करना चाहते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाने वाली है या नहीं ? छिपे गल्ले को निकालने की नीति बरती जायगी या नहीं । ऐसा कोई योजना आपके सामने है या नहीं या उसके बारे में सोचना चाहते हैं या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : यह बहुत ही मजेदार प्रश्न है और उपयोगी प्रश्न है । जहां कहीं भी अनाज जरूरत से अधिक है चाहे वह किसान के पास हो या व्यापारी के पास हो उसे को निकालना आवश्यक है और मैं फिर यह दोहराना चाहता हूं जिस बात को बार बार दोहराया है कि जो राज्य सरकार इस मामले में तीव्रता से कदम उठाएगी केन्द्र से उस को पूरा सहयोग दिया जायेगा । सदस्य महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बिहार सरकार में जो उन के दल के मंत्री हैं उन से जरा पूछें कि कि एक दफे जखीरेबाजों से गल्ला निकालने का कार्य शुरू करके बीच में क्यों छोड़ दिया गया ? क्या सेंटर से कोई रुकावट हुई उस मे, यह उन से जाकर पूछें ।

14.35 hrs.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume general discussion on the General Budget. Shri K. C. Pant may continue his speech.